



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 169]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 31, 1978/ज्येष्ठ 10, 1900

No. 169]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 31, 1978/JYAISTHA 10, 1900

इस भाग में मिनम पृष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

गृह मंत्रालय

(कार्यालय और प्रशासनिक सुधार विभाग)

प्रधिकारिता

नई दिल्ली, 31 मई, 1978

सा० का० नि० 311(अ) —केन्द्रीय सरकार, प्रधिकार भारतीय सेवा प्रथनियम 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा(1) द्वारा प्रवत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध राज्यों को परामर्श फरंते के पश्चात्, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का नाम प्रधिकार भारतीय सेवा (गृहनिर्माण कर्ज) नियम 1978 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की सारीख को प्रवृत्त होगे।

2. परिभाषा:—इन नियमों में, जब तक सदर्भ से प्रथमा परेक्षित न हो, “सेवा के सदस्य” से प्रधिकार भारतीय सेवा प्रथनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 2 से परिभाषित प्रधिकार भारतीय सेवा का सदस्य प्रभिप्रेत है।

3. गृह निर्माण कर्ज का विनियमन:—सेवा का कोई नवस्य ऐसी वरा पर और ऐसी एनों के प्रधीन गृहनिर्माण कर्ज की मजूरी का पात्र शोगा, जो केन्द्रीय सिविल सेवा समूह ‘क’ के प्रधिकारियों के सम्बन्ध में वेदांग भरकार द्वारा समय-ममत्य पर विनियिष्ट की जाए।

परन्तु ऐसा सदस्य ऐसी वरों पर और ऐसी शर्तों के अधीन मकान निर्माण कर्ज की मजूरी को चुन सकता है जो राज्य सिविल सेवा के श्रेणी-1 के प्रधिकारियों के उस राज्य भरकार ग्रथवा राज्य मरकारों द्वारा समय-ममत्य पर विनियिष्ट की जाए, जिनके संवर्ग में वह है।

4. निर्वचन:—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रस्तुत उठाव है तो उसे केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा और वह इसका विनियोग करेंगी।

[सं० 29019/1/76-प्र०भा०से०(ii)]

वी० क० शेरियन, डेस्क प्रधिकारी

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 1978

G.S.R. 311(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Governments of the States concerned, hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement:—(i) These rules may be called the All India Services (House Building Advance) Rules, 1978.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Definition :—In these rules, unless the context otherwise requires “member of the Service” means a member of an All India Service, as defined in section 2 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951).

3. Regulation of House Building Advance :—A member of the Service shall be eligible to the grant of House Building Advance at such rates, and subject to such conditions as may be specified by the Central Government from time to time in respect of officers of the Central Civil Services, Group ‘A’.

Provided that such member may elect to the grant of House Building Advance at such rates subject to such conditions as may be specified from time to time by the State Governments or State Governments on whose cadre he is borne in respect of officers of the State Civil Service, Class 1.

4. Interpretation :—If any question arises as to the interpretation of the rules, it shall be referred to the Central Government who shall decide the same.

[No. 29019/1/76-AIS(II)]

V. K. CHERIAN, Desk Officer.